(b) whether it is a act that Government propose to allow private sector to expand its production capacity by setting up new steel projects; and

(c) if so, what are the details thereof and the quantity of steel likely to be produced through private sector by the end of the Eighth Plan Period?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) The quantity of crude steel produced by the secondary producers during 1989-90 was 3.13 million tonnes and that by the Tata Iron & Steel Company Ltd. (TISCO) 2.32 million tonnes.

(b) and (c) It has been decided to allow creation of additional steel making capacity in the secondary sector with unit capacity upto one million tonne based on electric are furnace/energy optimising technologies including small blast furnaces. Entrepreneurs will have the option to decide the plant size keeping in view the product-mix and technology to be adopted. Six million tonnes of crude steel is expected to be produced by the secondary producers by the end of the Eighth Plan and 3.05 million tonnes by TISCO.

Refusal by POSCO to assist in setting up steel plant in Orissa

982. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pohang Steel Company (POSCO) of South Korea has refused to assist Government in setting up a steel plant at Paradeep in Orissa;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that Orissa Government has already started negotiation with other foreign countries for a second steel plant in the State; and

(d) if so, what are the details thereof?

MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) and (b) Government of India have not sought the assistance of Pohang Steel Corporation (POSCO) of South Korea for setting up a steel plant at Paradeep in Orissa.

(c) and (d) No formal proposal has been received from the Orissa State Government in regard to establishment of another steel plant in the State.

पटसन का उत्पादन

983. श्री राम जेठमलानी : सरदार अजीत सिंह अरोड़ा क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष पटसन का उत्पादन 68 लाख गांठों से अधिक होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पटसन उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये, सरकार ने भारतीय पटसन निगम के माध्यम से पटसन खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम ने इस वर्ष कितना पटसन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस प्रकार खरीदे गये पटसन का भंडारण करने के लिये की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री, साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीद के लिये जे०सी०आई० की एक उन्मुक्त नीति है, जिसके तहत निगम तथा इसके राज्य स्तरीय खरीद संगठनों को किसानों द्वारा कच्चे पटसन की जितनी भी मात्रा उपलब्ध कराई जाती

है उतनी इसके द्वारा खरीद ली जाती है । विगत की तरह ही जै०सी०आई० ने अपने अवस्थापना तंत्र जिसमें चालू मौसम के खरीद प्रचालन के लिये गोदाम संबंधी व्यवस्था भी शामिल है, को पहले ही सुदृढ़ कर लिया है ।

पूर्ति विभाग का विकेन्द्रीकरण

984. **श्री अजीत सिंह :**
श्री सुशील बरोपा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्ति विभाग के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने और इस विभाग को समाप्त करने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप व्यय में कितनी बचत होने का अनुमान है ;

(ग) क्या उक्त विभाग के विभिन्न अनुभागों का विकेन्द्रीकरण करने तथा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्यत्र खपाये जाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई हैं ?

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य योजना की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) पूर्ति विभाग/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का समापन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा मांग किए जाने वाले सामान और उपस्करों की केन्द्रीयकृत खरीद के संबंध में नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही हैं ।

(ख) इसके फलस्वरूप व्यय में होने वाली किफायत का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया हैं, नीति की समीक्षा की जा रही हैं । यदि इस समीक्षा के फलस्वरूप कुछ कार्य केन्द्रीयकृत क्रय एजेंसी (पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय) से अन्य मंत्रालयों को सौंपा जाता हैं, तो अन्य विभागों/मंत्रालयों को कार्य सौंपे जाने पर उनसे संबंधित कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण उन विभागों/मंत्रालयों को किए जाने का प्रस्ताव हैं ताकि नौकरी में उनकी पदोन्नति के अवसरों में कोई कमी न आए ।

(ङ) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी ।

Loss of deposits by SBI

985. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the 'Economic Times' dated the 23rd July, 1990 to the effect that the State Bank of Inda is losing huge deposits to other banks every day;

(b) if so, whether the reasons for the same have been ascertained;

(c) what steps Government propose to take to arrest such huge outflow of deposits from the State Bank of India; and

(d) whether the Reserve Bank will also prescribe a uniform rate of interest to be paid by the different banks including SBI to its depositors on terms deposits?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) The said news item refers to a decline in State Bank of India's deposits, allegedly in the wake of introduction of Certificate of Deposits (CDS). Banks are permitted to issue CDS within permissible limits which at